



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 25 राँची, मंगलवार 8 माघ 1935 (श०)
28 जनवरी 2014 (ई०)

वित्त विभाग

संकल्प

27 जनवरी, 2014

विषय: सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय के आप्त सचिव का अकार्यात्मक वेतनमान स्वीकृत करने के संबंध में।

संख्या-6/एस0-16(फि०क०)- 01/2009/283/वि०-- भारत सरकार, कर्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के आदेश संख्या 10 मार्च, 2004 c.s.(II)(PT-I) दिनांक 24 जून, 2005 के द्वारा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आप्त सचिव को दिनांक 01 जनवरी 1996 के प्रभाव से

वैचारिक रूप से तथा 03 अक्टूबर, 2003 से वास्तविक रूप से ₹0 8000-275-13500/- के अकार्यात्मक वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गयी है। यह पंचम वेतन आयोग के क्रम में की गई कार्रवाई थी।

2. भारत सरकार के उक्त निर्णय को दृष्टिगत में रखते हुये झारखण्ड सचिवालय के प्रशाखा पदाधिकारी एवं आप्त सचिव को वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2382/वि०, दिनांक 21 अगस्त, 2007 के द्वारा ₹0 8000-275-13500/- का अकार्यात्मक वेतनमान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया था।

3. छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा एवं भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), नई दिल्ली के अधिसूचना संख्या G.S.R.-622 (E) दिनांक 29 अगस्त, 2008 के द्वारा केन्द्रीय सचिवालय के प्रशाखा पदाधिकारी एवं आप्त सचिव के लिये चार वर्ष की कालावधि पूर्ण होने पर अकार्यात्मक वेतनमान PB-III ग्रेड वेतन 5400/- रुपये स्वीकृत किया गया है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सचिवालय के प्रशाखा पदाधिकारी/आप्त सचिव की भांति छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के परिप्रेक्ष्य में झारखंड सचिवालय के आप्त सचिव का चार वर्ष की कालावधि पूर्ण होने पर अकार्यात्मक वेतनमान PB-III ग्रेड वेतन 5400/- रुपये नहीं किया जा सका था।

4. अतः 6th PRC के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), नई दिल्ली के अधिसूचना संख्या G.S.R.-622 (E) दिनांक 29 अगस्त, 2008 के द्वारा केन्द्रीय केन्द्रीय सचिवालय के प्रशाखा पदाधिकारी एवं आप्त सचिव के लिये स्वीकृत अकार्यात्मक वेतनमान की भांति झारखंड सचिवालय के आप्त सचिव को आप्त सचिव के पद पर चार वर्षों की पूर्ण सेवा होने पर वेतनमान PB-III ग्रेड वेतन 5400/- रुपये में अकार्यात्मक वेतनमान स्वीकृत करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है।

5. अकार्यात्मक वेतनमान का लाभ दिनांक 01 जनवरी, 2006 के प्रभाव से प्रभावी होगा तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि० दिनांक 28 फरवरी, 2009 इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे तथा शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगे।

6. अकार्यात्मक वेतनमान में निर्धारित वेतन के परिप्रेक्ष्य में महंगाई भत्ता के आलावा अन्य देय भत्ते 01 जनवरी, 2014 से लागू होगा।

7. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक-3426/वि0, दिनांक-11 दिसम्बर, 2013 के क्रम में दिनांक 22 जनवरी, 2014 की बैठक के मद संख्या-10 में दी गई है।

आदेश:- आदेशा दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियां कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची सहित सभी विभाग/ विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (ले0 एवं हक0), झारखंड, रांची को प्रेषित की जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमरेन्द्र प्रताप सिंह,

सरकार के सचिव।
